



अहमदाबाद में बारूद बना मौत का जाल: पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोटों के बाद लगी आग, 8 की मौत, कई घायल; प्रधानमंत्री ने जताया शोक

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद से शनिवार को एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे की खबर सामने आई, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। शहर के महमूदपुरा क्षेत्र स्थित गैट्रेड रोड पर संचालित टैलेंट फायरवर्क्स नामक पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के भीतर रखे विस्फोटक पदार्थों में लगातार धमाके होने लगे। विस्फोटों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई किलोमीटर दूर तक उनकी आवाज सुनाई दी और आसपास की इमारतें तक कांप उठीं। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए, जबकि फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे कई मजदूर आग और धुएं के बीच फंस गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस भीषण हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया।



परिसर में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी रहा। हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार एलजी अस्पताल में पांच घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि सिविल अस्पताल में चार घायलों को भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीमें घायलों के उपचार में जुटी हुई हैं और गंभीर रूप से झुलसे मरीजों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, उसका संचालन मेहुल डोडिया नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में पटाखों और

दी ताकि बचाव कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। आसपास के क्षेत्रों को भी एहतियातन खाली कराया गया। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री में रखी ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि अधिकारी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विस्तृत जांच का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। पुलिस, फायर विभाग और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संयुक्त टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, अग्निशमन व्यवस्था पर्याप्त थी या नहीं तथा लाइसेंस और सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का अनुपालन किया गया था या नहीं। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुर्घटना को अत्यंत दुःखद बताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोककुल परिवारों के साथ

हैं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की। इस हादसे ने एक बार फिर पटाखा उद्योग में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक अग्निशमन उपकरणों का उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। फिलहाल दमकल विभाग आग पर पूरी तरह काबू पाने के साथ-साथ फैक्ट्री परिसर में फंसे लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। मलबे को हटाने का कार्य भी सावधानीपूर्वक किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीतर कोई संवेदनाएं शोककुल परिवारों के साथ

लाने तथा घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दुर्घटना में घायल सभी नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि राहत एवं पुनर्वास कार्य में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मृतकों के परिजनों तथा घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे, वहीं गुजरात सरकार की ओर से मृतकों के अश्रितों को चार-चार लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इससे मृतकों के परिजनों को कुल छह-छह लाख रुपये तथा घायलों को कुल एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

अमेरिका-ईरान टकराव ने बढ़ाई पश्चिम एशिया की चिंता: ईरान ने इस्लामाबाद समझौते की प्रतिबद्धताएं निलंबित कीं, खाड़ी देशों को दी कड़ी चेतावनी

तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे सैन्य तनाव के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए इस्लामाबाद समझौते के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को निलंबित करने की घोषणा की है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते की मूल शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए अब ईरान भी उसके प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इस फैसले के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक संबंधों और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ईरानी सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि वर्तमान हालात असाधारण हैं और देश पूरी तरह अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक क्षेत्र में तनाव कम नहीं होता और

सामान्य परिस्थितियां बहाल नहीं होतीं, तब तक इस्लामाबाद समझौते के तहत ईरान की सभी प्रतिबद्धताओं का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। गरीबाबादी ने कहा कि ईरान किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। उनके अनुसार, अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने क्षेत्र की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और ऐसे माहौल में पहले की तरह समझौते का पालन करना व्यावहारिक नहीं है। तनाव के बीच ईस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्पस (IRGC) ने भी कड़ा बयान जारी किया है। आईआरजीसी ने खाड़ी क्षेत्र के देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी देश की भूमि, हवाई क्षेत्र या सैन्य सुविधाओं का उपयोग ईरान के खिलाफ हमलों के लिए किया गया, तो उसे भी वैसी ही जवाबी कार्रवाइ का सामना करना पड़ेगा। आईआरजीसी ने कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और किसी भी हमले का जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा।

‘बागी लौट आए तो एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा’: अभिषेक बनर्जी का बड़ा राजनीतिक दांव, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांघट अभिषेक बनर्जी ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि उनके विरोध में पार्टी छोड़ने वाले सभी बागी नेता वापस तृणमूल कांग्रेस में लौट आते हैं, तो वह एक घंटे के भीतर अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान को बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान न केवल पार्टी छोड़ चुके नेताओं को संदेश देने की कोशिश है, बल्कि टीएमसी के भीतर संगठनत्वक एकजुटता का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने बिना किसी नेता का नाम लिए कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने ऐसे समय में तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा था, जब संगठन कठिन दौर से गुजर



रहा था और विभिन्न प्रकार के दबाव बनाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उस समय कई लोगों ने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी, जबकि हजारों कार्यकर्ताओं ने तमाम चुनौतियों के बावजूद पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और जनता के बीच रहकर संगठन को मजबूत बनाए रखा। अभिषेक बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि यदि वे सभी नेता, जिन्होंने अलग रास्ता चुना था, आज वापस पार्टी में शामिल हो जाएं तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी

पद से मोह नहीं है और पार्टी तथा संगठन उनके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि टीएमसी की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े रहकर संघर्ष किया। अपने भाषण के दौरान अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कुछ नेताओं पर प्रशासनिक और जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया गया, जिसके कारण उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। उनका आरोप था कि कुछ नेताओं को इस तरह की परिस्थितियों में पार्टी से अलग होने के लिए मजबूर किया गया। टीएमसी सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के नेताओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई। उनके अनुसार कुछ नेताओं को भाजपा के साथ जाने या अलग राजनीतिक गुट बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया कि ऐसे नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से राहत मिलने का भरोसा दिया गया और बदले में उनसे तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बयान देने तथा पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने के लिए कहा गया। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में किसी विशेष मामले या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान ऐसे समय अला है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में दल-बदल, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं।

‘वंदे मातरम’ के साथ अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान: स्काईरूट एयरोस्पेस ने रचा इतिहास, विक्रम-1 बना देश का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट

श्रीहरिकोटा। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के सामने अपनी तकनीकी क्षमता का नया परिचय दिया है। देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने शनिवार को अपने पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल ‘विक्रम-1’ का सफल प्रक्षेपण कर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ दिया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने वाला विक्रम-1 भारत की भरती से लॉन्च होने वाला पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बन गया। इस सफलता को भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए मील का पथर माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट संकेत मिला है कि अब भारतीय निजी कंपनियां भी उपग्रह प्रक्षेपण और उन्नत अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मिशन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को कानपुर से भैकनिक प्रतिभा, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया हुए कहा कि यह केवल एक रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं, बल्कि नए भारत की तकनीकी शक्ति और युवा क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को ‘वंदे मातरम मिशन’ की संज्ञा देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल अंतरिक्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि भारत माता की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, युवाओं में विज्ञान

और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर प्रश्न उठाए जाते थे, लेकिन आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल सकारात्मक संस्थानों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भी विश्वस्तरीय अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने की क्षमता रखता है। इस ऐतिहासिक मिशन की सबसे विशेष बात यह रही कि विक्रम-1 अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा ‘वंदे मातरम’ संदेश भी पृथ्वी की कक्षा में लेकर गया। प्रधानमंत्री के हस्तालिखित संदेश वाले पोस्टकार्ड के अलावा भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन का हिस्सा बनाए गए। यह पहल केवल तकनीकी उपलब्धि तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे भारत की वैज्ञानिक यात्रा और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना वर्ष 2018 में पवन कुमार चंदना और उनकी टीम ने की थी। पवन चंदना इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक के रूप में पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से भैकनिक प्रतिभा, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया हुए कहा कि यह केवल एक रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं, बल्कि नए भारत की तकनीकी शक्ति और युवा क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को ‘वंदे मातरम मिशन’ की संज्ञा देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल अंतरिक्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि भारत माता की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, युवाओं में विज्ञान

और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर प्रश्न उठाए जाते थे, लेकिन आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल सकारात्मक संस्थानों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भी विश्वस्तरीय अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने की क्षमता रखता है। इस ऐतिहासिक मिशन की सबसे विशेष बात यह रही कि विक्रम-1 अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा ‘वंदे मातरम’ संदेश भी पृथ्वी की कक्षा में लेकर गया। प्रधानमंत्री के हस्तालिखित संदेश वाले पोस्टकार्ड के अलावा भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन का हिस्सा बनाए गए। यह पहल केवल तकनीकी उपलब्धि तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे भारत की वैज्ञानिक यात्रा और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना वर्ष 2018 में पवन कुमार चंदना और उनकी टीम ने की थी। पवन चंदना इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक के रूप में पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से भैकनिक प्रतिभा, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया हुए कहा कि यह केवल एक रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं, बल्कि नए भारत की तकनीकी शक्ति और युवा क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को ‘वंदे मातरम मिशन’ की संज्ञा देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल अंतरिक्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि भारत माता की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, युवाओं में विज्ञान

और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर प्रश्न उठाए जाते थे, लेकिन आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल सकारात्मक संस्थानों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भी विश्वस्तरीय अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने की क्षमता रखता है। इस ऐतिहासिक मिशन की सबसे विशेष बात यह रही कि विक्रम-1 अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा ‘वंदे मातरम’ संदेश भी पृथ्वी की कक्षा में लेकर गया। प्रधानमंत्री के हस्तालिखित संदेश वाले पोस्टकार्ड के अलावा भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन का हिस्सा बनाए गए। यह पहल केवल तकनीकी उपलब्धि तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे भारत की वैज्ञानिक यात्रा और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना वर्ष 2018 में पवन कुमार चंदना और उनकी टीम ने की थी। पवन चंदना इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक के रूप में पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से भैकनिक प्रतिभा, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया हुए कहा कि यह केवल एक रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं, बल्कि नए भारत की तकनीकी शक्ति और युवा क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को ‘वंदे मातरम मिशन’ की संज्ञा देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल अंतरिक्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि भारत माता की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, युवाओं में विज्ञान

गरवी गुजरात

हिन्दी

JioTV

CHENNAL NO. 2002

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये



देश का सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य बना गुजरात, नीति आयोग के 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' में नंबर-1

► 56.6 के सर्वोच्च स्कोर के साथ गुजरात देश में पहले स्थान पर, महाराष्ट्र (53.7) और तमिलनाडु (53.3)

क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर

► उद्योग-अनुकूल नीतियां, iNDEXTb की

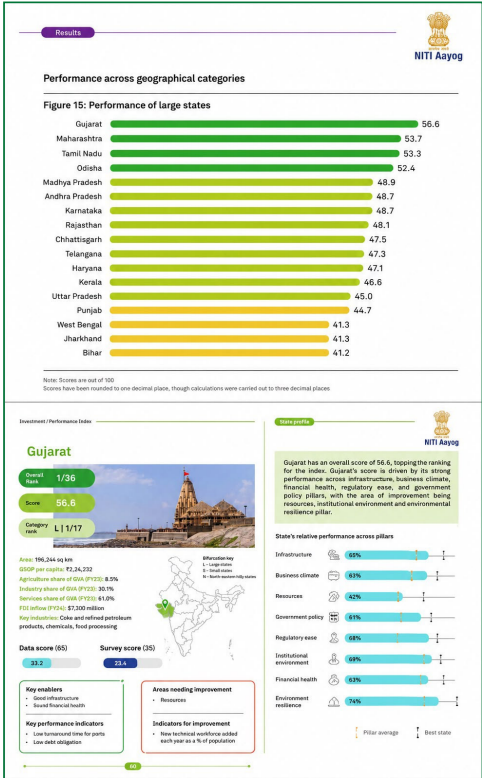
सिगल-विंडो व्यवस्था और प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक इकोसिस्टम ने गुजरात को बनाया निवेशकों की पहली पसंद

▶ औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली राष्ट्रीय औसत से लगभग 29% सस्ती, औसतन 23.8 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति

▶ भारत के कुल मर्चेंडाइज निर्यात में 31% हिस्सेदारी, प्रति व्यक्ति GSDP 2.64 लाख; राजकोषीय घाटा केवल 2.81% और कुल देनदारियां बड़े राज्यों के औसत से लगभग 40% कम

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने की दिशा में गुजरात ने निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' में गुजरात

ने 56.6 के सर्वोच्च स्कोर के साथ बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। 17 प्रमुख राज्यों के मूल्यांकन में गुजरात ने महाराष्ट्र (53.7) और तमिलनाडु (53.3) को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की है।



मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों, प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था

Extension Bureau) निवेशकों को सिंगल-विंडो क्लियरेंस के

साथ एंड-टू-एंड सहायता उपलब्ध करता है, जिससे निवेश प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सरल बनी है। इसके अतिरिक्त, व्यवसायों के लिए उचित लागत और समय पर NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने की एक अत्यंत सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया है, जो 'ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देती है। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि सरकार द्वारा अनिवार्य सेवाओं पर हड़ताल पर प्रतिबंध के कारण राज्य में 'लेबर डिस्रप्शन' (श्रम व्यवधान) का प्रभाव न के बराबर है। यह व्यवसायों को एक बेहद सुस्थित और स्थिर लेबर माहौल प्रदान करता है।

विश्वस्तरीय औद्योगिक
इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लाग-एंड-प्ले
इकोसिस्टम और 'वाइब्रेंट
गुजरात' से बढ़ा निवेश आकर्षण
रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात का मजबूत औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों के भरोसे का प्रमुख आधार है। धोलेरा, SIR, GIFT City, साणंद, दाहेज, झगडिया और सायखा जैसे आधुनिक औद्योगिक क्लस्टर निवेशकों को विश्वस्तरीय प्लाग-एंड-प्ले सुविधाएं

उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उद्योगों की स्थापना और संचालन अधिक तेज एवं सुविधाजनक हुआ है। इसी मजबूत इकोसिस्टम के बल पर राज्य का द्विवार्षिक 'वाइब्रेंट गुजरात समिट' घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से भारी निवेश प्रतिबद्धताओं को आकर्षित करने में बेहद सफल रहा है।

लॉजिस्टिक्स और कनिष्ठविद्यार्थी के क्षेत्र में भी गुजरात ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्य में देश के कुल स्टूडेंट्स हाईवे नेटवर्क का लगभग 10% हिस्सा है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग चार गुना है। राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे की सर्वाधिक अनुमानित लंबाई (635 किलोमीटर) गुजरात में है, जबकि देश के राज्य रेलवे नेटवर्क का 7% हिस्सा भी राज्य में स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार, कम टर्नआराउंड टाइम और बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता ने सफ्टवेयर चैन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया है। 29% सस्ती विजली और निर्यात आपूर्ति ने उद्योगों को दिया लागत लाभ

रिपोर्ट में गुजरात के पावर सेक्टर को भी निवेश आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बताया गया है। राज्य

में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत राष्ट्रीय औसत से लगभग 29% कम है। वहीं, औसतन 23.8 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, जो बड़े राज्यों के औसत से अधिक है। प्रतिस्पर्धी बिजली दरों और विश्वसनीय आपूर्ति ने राज्य को उद्योगों के लिए अधिक आकर्षक बनाया है।

31% निर्यात हिस्सेदारी,
MSME इकोसिस्टम और
मजबूत वित्तीय अनुशासन बने
निवेश का आधार

पोर्टों के अन्तसार, गुजरात की मजबूत आर्थिक बुनियाद भी निवेशकों के विश्वास का प्रमुख कारण है। भारत के कुल मचेंडाइन निर्यात में राज्य की 31% हिस्सेदारी है, जबकि वित्त वर्ष 2019-2024 के दौरान गुजरात की GDP वृद्धि दर देश में तीसरे स्थान पर रही। राज्य का प्रति व्यक्ति GDP 2,64,232 है, जो बड़े राज्यों के औसत से 67% अधिक है। इसके साथ ही, गुजरात के MSME बेस में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSEs) का एक बहुत ही स्वस्थ अनुपात है (जिसमें यह पूरे देश में चौथे स्थान पर है) जो राज्य

मैं एक अत्यंत गतिशील और लचीला औद्योगिक इकोसिस्टम बनाता हूँ। वित्तीय प्रबंधन के मामले में भी गुजरना न उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2024 में राज्य का राजकोषीय घाटा GDP का केवल 2.81% रहा, जो सभी राज्यों में सबसे कम है। वहाँ, राज्य की कुल देनदारियाँ लगभग 18% हैं, जो बड़े राज्यों के औसत से करीब 40% कम हैं। यह मजबूत वित्तीय अनुशासन निवेशकों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता का संकेत देता है।

614 अटल टिकरिंग लैन्स ने नवचार आधारित औद्योगिक इकोसिस्टम को दी महजुबती रिपोर्ट में गुजरात के नवचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी निवेश अकरण का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। वित्त वर्ष 2025 तक राज्य में 614 अटल टिकरिंग लैन्स (ATLs) स्थापित की जा चुकी है। प्रति एक लाख आबादी पर 1.24 ATLs के साथ गुजरात बड़े राज्यों के औसत से लगभग 19% आगे है, जिससे नवचार आधारित उद्योगों और भविष्य की तकनीकों के लिए महजुब आधार तैयार हुआ है।

समुद्र तटीय क्षेत्रों के सिंह नीलगाय और जंगली सूअरों के शिकार पर निर्भर : सिंह केवल पालतू पशुओं का ही शिकार करके जीवित रहते हैं; इस धारणा को नए अध्ययन ने गलत सिद्ध किया

▶ **सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में लगभग 100 सिंहों का निवास। गिर वन के बाहर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले सिंह खेती की फसलों को नुकसान पहुँचाने वाली नीलगायों तथा जंगली सूअरों का शिकार करके किसानों के सच्चे मित्र बने**

▶ **अंतरराष्ट्रीय पीयर-रिव्यूड जर्नल 'कंजर्वेशन' में प्रकाशित शोध में पता चला है कि तटीय क्षेत्रों के सिंहों द्वारा किए जाने वाले कुल शिकार में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा वन्य जीवों के शिकार का है, अर्थात् ये सिंह नीलगाय, जंगली सूअर तथा आवारा पशुओं का शिकार करते हैं**

▶ **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विश्व में एशियाई सिंहों के एकमात्र अंतिम आश्रय स्थल गिर में सिंहों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए 'प्रोजेक्ट लायन' शुरू किया है**

▶ **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए लगातार समर्पित प्रयास किए हैं और उनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं**

▶ **“यह शोध अध्ययन दर्शाता है कि गिर वन के बाहर रहने वाले सिंह नीलगाय तथा जंगली सूअरों का शिकार करके यहाँ के किसानों को लाभ पहुँचाते हैं। नीलगायों तथा जंगली सूअरों की आबादी पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण रखकर सिंह खेती की फसलों को होने वाले नुकसान को कम करते हैं और किसानों की सहायता करते हैं”, श्री अर्जुन मोहवाडिया, वन एवं पर्यावरण मंत्री, गुजरात**

गांधीनगर : यदि आप किसी से भी पूछें कि सिंह गिर वन्यजीव अभयारण्य के बाहर निकलकर समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में मुक्त रूप से क्यों घूम रहे हैं, तो सबसे सामान्य उत्तर यही मिलेगा कि जंगल के बाहर पालतू पशु बाढ़ी संख्या में होते हैं, इसलिए सिंह जूट जाते हैं और उन्हीं पालतू पशुओं का शिकार करके जीवित रहते हैं। हालाँकि, हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह धारणा गलत सिद्ध हुई है।

इस अध्ययन में खुलासा हुआ है कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले एशियाई सिंह पालतू पशुओं की अपेक्षा वन्यजीवों के शिकार पर अधिक निर्भर हैं। ये निष्कर्ष उस व्यापक धारणा को गलत सिद्ध करते हैं कि गिर के जंगलों के बाहर रहने वाले सिंह अपने अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से पालतू पशुओं पर निर्भर हैं।

वर्ष 2025 में आयोजित 16वीं सिंह गणना के अनुसार वर्तमान में गुजरात में 891 एशियाई सिंह हैं। यह संख्या गुजरात की वन्यजीव संरक्षण नीति की सफलता

को सिद्ध करती है।
अंतरराष्ट्रीय प्रीयर-रिव्यूड जर्नल
कन्वेंशन में पीयारसिंह शोध में पता चला
है कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के सिंहों द्वारा
किए जाने वाले कुल शिकार (बायोमास)
में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा वन्यजीवों
से प्राप्त होता है, जो गिर संरक्षित क्षेत्र
के बाहर भी सिंहों के विस्तारित हो रहे
आवास का श्रेष्ठ इकोलॉजिकल स्वास्थ्य
का संकेत देता है।
जुनागढ़ वन वृक्ष के वन संरक्षक तथा
इस अध्ययन के सह-लेखक श्री मोहन
राम ने कहा कि, “हमारे अध्ययन में मार्च
और अप्रैल 2024 के दौरान जुनागढ़,
गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और
पोरबंदर के तटीय जिलों से एकत्र किए
गए सिंहों के मल के 160 नमूनों का
विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में
पता चला कि सिंहों के आहार का 64
प्रतिशत हिस्सा नीलगाय तथा जंगली
सूअर जैसे वन्य जीवों का था, जबकि
आवारा पशुओं का हिस्सा केवल 31
प्रतिशत था।”
श्री मोहन राम ने जोड़ा, “सभी शिकारी

प्रजातियों में नीलगाय सिंहों के भोजन का प्रमुख स्रोत है, जो काले उपभोग (विष) का बायोमास के अनेक से अधिक (15%) प्रोटीन। हिस्सा रखती है। जंगली सुआर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वन्य शिकार था, जबकि आकार परशुओं में गाय तथा भैंस आदि का सबसे बड़ा हिस्सा था।¹

डायरी पैरेंट ऑफ एशियाटिक लायन्स इन द कोस्टल इकोसिस्टम ऑफ सौराष्ट्र, गुजरात, इंडिया² शीर्षक वाला उद्योग अध्ययन मोहवाडिया, आराधना साहू, नित्यानन्द श्रीवास्तव, कृतज्ञा धर, रशित चौधरी और लहर झाला द्वारा तैयार किया गया है तथा यह कंजवेंशन जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

गुजरात के वन एवं पर्यवरण मंत्री श्री अनुज मोहवाडिया ने कहा, "74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई सिंहों के दीर्घकालीन संरक्षण एवं सुरक्षा पर केन्द्रित महत्वाकांक्षी पहल 'प्रोजेक्ट लायन' शुरू की थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लगातार

समर्पित प्रयास किए हैं।”
श्री अर्जुन मोहब्बतिया ने आगे जोड़ा,
“यह शोध अध्ययन स्पष्ट करता है कि
गिर के जंगलों के बाहर सिंहों की आबादी
नीलागय तथा जंगली सूअर जैसे फसलों
को नुकसान पहुँचाने वाले प्राणियों का
शिकार करके किसानों की सहायता
कर रही है। इन प्राणियों की आबादी पर
प्राकृतिक नियंत्रण रखकर सिंह फसलों
को होने वाले नुकसान को कम करते
हैं।”

“महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव आबादी के बीच रहने के बावजूद सिंह मुख्य रूप से प्राकृतिक शिकार पर ही निर्भर रहे हैं। गुजरात में सिंह संरक्षण का यह सफल मॉडल विश्वभर में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक उदाहरण माना जाता है,” वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण माली ने कहा।

शरण के विपरीत अन्यत्र आया
इस घोष के शोचनार्थी मूल धारणा
के से विकलुत विपरीत हैं। शोचनार्ताओं का
पले यह मानना था कि मानव आबादी
वाले तट क्षेत्रों में वन्यजीवों का कमी
होने के कारण सिंह पालतू पशुओं पर
अधिक निर्भर होंगे, पुत्र अथयन के
क्षेत्रों बताते हैं कि गुजरात के तटीय
क्षेत्रों में नीलायन और जंगली सुअरों की
स्वस्थ आबादी सिंहों को अधिकांशतः
प्राकृतिक शिकार कर ही पारिणामरुप में
सहायता कर रही है। परिणामरुप में
पालतू पशुओं पर दबाव कम हो सकता

है और मानव-सिंह संघर्ष को टाला जा सकता है।

शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि समुद्र तटीय इकोसिस्टम अब एशियाई सिंहों की तीन महत्वपूर्ण सैटेलाइट आबादियों को आश्रय देता है: दक्षिण-पश्चिम तटीय पट्टी, दक्षिण-पूर्व तटीय पट्टी तथा भावनगर की तटीय पट्टी। ये तीनों क्षेत्र सिंहों के विस्तारित हो रहे साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं।

इस अध्ययन के अनुसार, सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में 100 से अधिक सिंह निवास करते हैं और पम्प रहे हैं। यह स्थिति गुजरात के दीर्घकालीन संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रमाण है।

आवारा और छोड़ दिए गए पशु सिंहों का आसान शिकार

इस अध्ययन के अनुसार तटीय क्षेत्रों के सिंहों का भोजन मुख्यतः नीलगाय और जंगली सुअरों पर केन्द्रित है। यह तथ्य दर्शाता है कि शिकार की प्रचुरता और आवास की गुणवत्ता सिंहों की भोजन संबंधी अदतों पर गहरा प्रभाव डालती है। शोधकर्ताओं ने अवलोकन किया कि गाय और बैस सिंहों के भोजन का हिस्सा अवश्य है, लेकिन इनमें से अधिकांश पशु आवारा, छोड़ दिए गए (निःशक्त) पशु अथवा जंगली नन चुके पशु होते हैं।

सौराष्ट्र के कुछ भागों में दूध न देने वाले वृद्ध पशुओं को छोड़ देने की प्रथा के कारण पैसे पशु बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। सिंहों के लिए ये पशु आसान शिकार बनते हैं।

► भविष्य की पीढ़ी और जमीन, दोनों के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

► मुख्यमंत्री ने जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाने और रोगमुक्त समाज के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया

► श्री भूपेंद्र पटेल ने साधारण ग्रामजन की तरह खाट पर बैठकर ग्रामीणों और किसानों के साथ सहज संवाद किया

► प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'बैक टू बेसिक' के विचार को ग्रामीण किसानों तक पहुंचाने का मुख्यमंत्री का अभिनव प्रयोग : प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों का प्रत्यक्ष दौरा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'बैक टू बैसिक' यानी अपनी जड़ों की ओर लौटने के विचार को ग्रामीण किसानों तक व्यापक रूप से पहुंचाने का अभियान दृष्टिकोण अपनाया है।

नए सदस्य में मुन्धुखमत्री ने गांधीनगर तहसील के महुन्ड्रा गांव के प्राकृतिक खेती करने वाले एक प्रतिनिधिल युवा किसान अल्देश पटेल के मॉडल फार्म का दौरा किया। उन्होंने गौशाला में गायों के रखरखाव और गाय-आधारित प्राकृतिक खेती की जानकारी प्राप्त करने में गहरी रुचि दिखाई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्राकृतिक फार्म का दौरा किया और महुन्ड्रा के ग्रामजनों के साथ खाट पर बैठकर एक साधारण ग्रामीणी की तरह प्रेरणादायी सहज संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा हमारी भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती ही सही विकल्प है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि यह रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले गंभीर रोगों से मानव स्वास्थ्य को बचाने और मानव जाति तथा जलमयि की सहेत को सुधारने का सेवा यज्ञ है।

जमीन के गिरते स्थायित्व पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज जमीन में कार्बन की मात्रा वित्ताजनक रूप से कम हो गई है। जमीन और मानव शरीर, दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र मयबूत विकल्प है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से प्राकृतिक किसानों के रक्षकण की जिम्मेदारी उठाने का अनुरोध किया।

पानी की कमी और अनियमित बारिश की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देशभर में चल रहे 'अमृत सरोवर' और 'खेत तालाब' के अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुधारमा सुलभता जैसी योजनाओं के तहत पहले नर्मदा पाइपलाइन के तीन किलोमीटर के दूजाल में आगे वाले तालाबों को ही भरा जाता था। अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 7 किलोमीटर कर दिया है।

प्रधानमंत्री द्वारा शुक्रवार को ही शुरू की गई हाइड्रोजन ट्रेन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज, जब पूरी दुनिया पूरी एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रही है, तब भारत भी इस क्षेत्र में किसी से पीछे रहने वाला नहीं है।

मुख्यमंत्री ने दैनिक जीवनशैली में भी पर्यावरण हितैषी बदलाव लाने की अपील की। उन्होंने सब्जी इत्यादि वस्तुओं की बिक्री के लिए प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कागज की थैलियों (पेपर बैग) का उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग एवं पर्यावरण, दोनों का समान रूप से ख्याल रखते हुए संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संवाद कार्यक्रम के दौरान प्राकृतिक खेती करने वाले प्रतिनिधिल किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और दूसरे किसानों की भी रसानुभव मुक्त प्राकृतिक खेती को ओगे मुड़ने की प्रेरणा दी। किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों एवं सरकारी अधिकारियों की ओर से मिल रहे लगातार मार्गदर्शन की सराहना भी की।

मुख्यमंत्री ने शिवपुर कंमा में प्रागतिशील किसान श्री शांतिलाल पटेल के मॉडल फार्म का भी दौरा किया।

इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव और आर.सी. मीणा, प्रभारी कलेक्टर श्री जे.एस. प्रतापजित, जिला किसान अधिकारी श्री हसरत जैसूनिन, जिला कृषि अधिकारी श्री शशिकांत पटनायक, जिला बागवानी अधिकारी सुश्री हेलनबन और 'आत्मा' के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री चर्मोरा सहित स्थानीय अग्रणी और बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामजन मौजूद रहे।

सूरत में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में वीवर्स परामर्श महासम्मेलन आयोजित हुआ

▶ सरकारी प्रोत्साहनों और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वस्त्र उद्योग वैश्विक बाजार में नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा : उप मुख्यमंत्री
 ▶ उप मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल और हाई क्वालिटी वाले 'वैल्यू एडिशन' उत्पादों पर जोर देने का अनुरोध किया
 ▶ सूरत में आगामी समय में 10 से 15 हजार नए एयर जेट लूम मशीनें संचालित होंगी

गांधीनगर : विश्वभर में टेक्सटाइल नगरी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले सूतक शहर में वस्त्र उद्योग के सतत विकास और आधुनिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से सूरत के संघनिया हेमाद में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में 'सिखोर एयरसेट वीवर्स एसोसिएशन' द्वारा 'वीवर्स परामर्श महासम्मेलन' आयोजित किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजराती जिस बाजार में कदम रखते हैं, वह बाजार हमारा बन जाता है। व्यावसायिक सफलता गुजरातियों के खून में है। एयर जेट के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। उन्होंने विश्ववास व्यक्त किया कि आगामी पाँच वर्षों में विश्व में सबसे अधिक एयर जेट मशीनें हमारे सूरत में संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रोत्साहनों और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वस्त्र उद्योग वैश्विक बाजार में नई

ऊँचाई को प्राप्त करेगा।
 पर्वतारोह अनुकूल और हाई वॉकलीवली
 वाले 'वैल्यू एडिशन' उत्पादों पर जोर
 देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि
 उद्योगकारों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके
 रहने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तथा
 हाई वॉकलीवली वाले वैल्यू एडिशन युक्त
 उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
 उन्होंने सूरत के टेम्सस्टील उद्योगकारों
 की साहसिकता की सराहना करते हुए
 कहा कि सूरत हमेशा नई टेक्नोलॉजी
 अपनाने में अग्रसर रहा है, जिसका
 उदाहरण उदाहरण वर्तमान में संचालित
 लाभाग 30 हजार वर्गफुटनिर्माण 'एयर
 जेट लूस' मशीन है। उद्योगकारों के
 सकारणक दृष्टिकोण और अनुकूल
 वातावरण के कारण आगामी एक वर्ष में
 ही सूरत में 10 से 15 हजार नई एयर जेट
 मशीनें संचालित होंगी, जिससे रोजगार
 और उत्पादन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान
 स्थापित होंगे।

सरकार उद्योगकारों के साथ खड़ी है, यह विश्वास दिलाते हुए श्री हर्ष संघवी ने कहा कि टेक्स्टाइल सेक्टर को प्रोत्साहन देने वाली सरकारी योजनाओं का अधिकतम



लाभ सुदूरवर्ती
वीवस तक
पहुँचाया जाएगा।
सूरत के कपड़े को
वैश्विक स्तर पर
बड़ा बाजार मिले,
इसके लिए भविष्य
में 'एक्सपोर्ट
फे सीरील टेशन न'
ओर 'कलस्टर
डेवलपमेंट' पर
विशेष ध्यान दिया
जाएगा। साथ ही
उन्होंने देश के
विभिन्न राज्यों
से रोजगार के
लिए सूरत आकर
स्थायी रूप से बसे
नागरिकों के सपनों
को साकार करने में
योगदान देने वाले सभी लोगों का आभार

व्यक्त किया।
राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का जो जनकारी देते हुए श्री संघवी ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत केवल एक वर्ष में गुजरात के व्यापारियों को 8 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज बनाते हुए पहले एमएसएमई के अंतर्गत प्रतिदिन 170 फाइलें स्वीकृत होती थीं, जो अब बढ़कर 397 हो गई हैं। आने वाले समय में प्रतिदिन 500 व्यापारियों को प्रोत्साहन राशि सौधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि हाल में 'पीएम मित्रा पार्क' की डेडर प्रक्रिया चल रही है, जिससे दक्षिण गुजरात में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इको-सिस्टम विकसित करने के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री ने उद्योगकारों से वैसी एडिशन के साथ गार्मेंटिंग क्षेत्र की और आगे बढ़ने का अनुरोध किया और दृढ़

विश्वास व्यक्त किया कि सूरत सहित पूरा दक्षिण गुजरात देश का सबसे बड़ा गार्मेंट्स हब बननेगा।

इस परामर्श महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सूरत में तेजी से बढ़ते एयर जेट लूम उद्योग के विस्तार, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने तथा वस्त्र उद्योग में वैश्व्य एडिशन बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर सूरत की पकड़ को और मजबूत बनाना है।

इस महासम्मेलन में सितकोर एयरजेट वीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मरूपभाई धोत्रिया, ग्रीनलेब डायमंड के अध्यक्ष श्री मुकेशभाई पटेल, गोल्ड्री सोलर के अध्यक्ष श्री ईश्वरभाई धोलकिया, फोस्टा के अध्यक्ष श्री कैलाश हकीम, अग्रणी श्री मनहरभाई सांचपरा, श्री सदीपभाई केडिया, ओथीगिक जोन आयुक्त श्री जे. पी. दवे सहित टेक्सटाइल उद्योग के अन्य, वीवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, व्यापारी मित्र तथा बड़ी संख्या में उद्योगकार उपस्थित रहे।

गुजरात पुलिस के प्रदर्शन पर सवाल: अपराधियों के सार्वजनिक जुलूस से कहीं अधिक सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक है

निर्भीक, निष्पक्ष, निष्पक्ष छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत. गुजरात में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लतीफ गिरोह ने लंबे समय तक गुजरात में एक आपराधिक साम्राज्य कायम रखा था, जिसमें हत्या, अपहरण, चोरी, सार्वजनिक रूप से शराब पीना और जुआ खेलना, जबरन वसूली और किसी की संपत्ति पर कब्जा करना शामिल था। एक ओर गुजरात में पोरबंदर के सरवन मूंजा और भूरा मूंजा के गिरोह और उनके साथी हत्या, अपहरण, चोरी, जबरन वसूली, सार्वजनिक रूप से शराब पीना और जुआ खेलना, जबरन वसूली करना और किसी की संपत्ति को लंबे समय तक हड़पना जैसे विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे। लेकिन उस समय के अधिकारी, गृह मंत्री और सरकार उस समय के बहादुर अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्णय लेते थे। एक बार अहमदाबाद में, जब छोटे-बड़े कांस्टेबल और अधिकारी लतीफ के दरियापुर पोपटियावाड़ इलाके में अपराधियों को उनके घरों पर बुलाने या गिरफ्तार करने गए, तो पुलिस लतीफ के गिरोह और उसके साथियों से डरती थी। लेकिन सरकार की मदद से, महिला आईपीएस अधिकारी गीता जोहरी जैसी बहादुर अधिकारियों ने, महिला होने के बावजूद, लतीफ के घर में घुसकर उसे कॉलर पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के पुलिस अधिकारियों में ए.के. सुर्लेलिया, आशीष भाटिया, पी.के. दत्ता,

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ‘मातुश्री मणीबेन मावजीभाई स्वरूपचंद वोरा वीबीसी भवन’ का लोकार्पण किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में शनिवार को श्री कच्छ वागड़ वे चौबीसी स्थानकवासी जैन विशा श्रीमाळी समाज (वीबीसी समाज) द्वारा नवनिर्मित ‘मातुश्री मणीबेन मावजीभाई स्वरूपचंद वोरा वीबीसी भवन’ का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने समग्र भवन का वर्चुअल टूर कर वहीं उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा समाज के सस भगीरथ कार्य की सराहना की। इस अवसर पर वेंजलपुर के विधायक श्री अमितभाई ठाकोर भी उपस्थित रहे।

सामाजिक उत्तरदायित्व की परंपरा को और सुदृढ़ बनाते हुए वीबीसी समाज की ओर से राज्य की बेटियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम ‘मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि’ योजना में 1,11,111 रुपए का चेक सहयोग स्वरूप मुख्यमंत्री को भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर वीबीसी समाज के उत्साह एवं एकता की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज का कोई भी व्यक्ति आर्थिक कठिनायों के कारण वंचित न रहे; इसके लिए इस समाज ने हमेशा प्रगतिशील प्रयास किया है। अहमदाबाद के हृदय समान जोधपुर क्षेत्र में इस भव्य भवन का निर्माण वास्तव में गौरव की बात है।

हाल ही में मनाई गई आषाढ़ी दूज और कच्छी नववर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम

- » अंत्योदय अन्न योजना तथा प्रायोरीटी हाउसहोल्ड परिवारों को वितरित किए जाने वाले गेहूँ तथा चावल पर राशन की दुकान के संचालकों को चुकाए जाने वाले कमीशन में वृद्धि
- » उचित मूल्य की दुकान के संचालकों का कमीशन 150 रुपए से बढ़ाकर 185 रुपए करने को मंजूरी दी गई
- » राज्य के 17,000 से अधिक राशन दुकानदारों को मिलेगा सीधा लाभ

गांधीनगर, : गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 अंतर्गत सभी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्रायोरीटी हाउसहोल्ड (पीएचएच) परिवारों को वितरित किए जाने वाले गेहूँ और चावल पर उचित मूल्य (राशन) की दुकानों के संचालकों को चुकाए जाने वाले कमीशन में वृद्धि की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन की दुकानों के संचालकों को अब तक गेहूँ व चावल वितरण पर प्रति किंटोल 150 रुपए कमीशन का भुगतान किया जाता था, जिसमें 35 रुपए की वृद्धि की गई है। इस प्रकार; अगर राशन

सतीश वर्मा, तरुण बरोट, कुलदीप शर्मा जैसे कुछ बहादुर अधिकारियों के नाम पर अपराधियों के मूत्र के नमूने जारी किए गए। गुजरात में शंकरसिंह वाघेला की सरकार के दौरान लतीफ का एनकाउंटर हुआ और उसके गिरोह और साथियों को लंबे समय तक जेल में रखा गया। कुछ अपराधी आज भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसी तरह, बहादुर अधिकारी सतीश वर्मा को पोरबंदर में सरवन मूंजा और भूरा मूंजा के गिरोहों का सफाया करने के लिए नियुक्त किया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री और सरकार ने गिरोहवार और उत्याती तत्वों को जेल में डाल दिया। आज तक लतीफ गिरोह और पोरबंदर गिरोह के साथियों ने किसी अपराध का जिक्र तक नहीं किया है। छोटे-बड़े अपराधी बातचीत में कहते थे, “मैं लतीफ गिरोह का सदस्य हूँ या पोरबंदर गिरोह का सदस्य हूँ।” वे उनके आशीर्वाद या निर्देशों पर आपराधिक गतिविधियाँ करते थे। लेकिन आज तक गुजरात में ऐसा कोई गिरोह सक्रिय नहीं है।

उस दौर के अपराधी हत्या, अपहरण, चोरी, जबरन वसूली, सार्वजनिक रूप से शराब पीना, जबरन वसूली और संपत्ति हड़पने जैसे अपराधों के लिए सार्वजनिक रूप से अपराधियों का जुलूस नहीं निकालते थे। वे अपराधियों को हिरासत में लेते थे या उनसे अपराध कबूल करवाने के लिए अन्य तृतीय-श्रेणी की सजाओं का इस्तेमाल करते थे। वे उन्हें विशेष सेवाएं/उपचार देते थे ताकि वे



भविष्य में कोई अपराध न करें। लेकिन यह सब बंद कमरे में होता था। वे ऐसा सार्वजनिक रूप से ‘सिंचम’ बनने या अपनी प्रशंसा के लिए नहीं करते थे। वे गुजरात सरकार की नजर में अच्छा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य

के लिए काम करते थे। वे अपने कर्तव्य का पालन करते थे। वे इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि गुजरात के किसी भी शहर में अशांति न फैले। ऐसे बहादुर अधिकारी कभी भी सार्वजनिक समारोहों में नहीं जाते थे, फोटो सेशन नहीं करते थे, रैलियां नहीं निकालते थे या किसी भी तरह का प्रचार नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान एसओजी डीसीपी आईपीएस अधिकारी राजदीप सिंह नाकुम द्वारा छोटे-बड़े अपराधियों का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालना एक आईपीएस

वैवाहिक जीवन में माता-पिता का सीमित हस्तक्षेप आवश्यक है, समुदाय के नेताओं ने परिवार में शांति बनाए रखने की अपील की है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत हमारे समाज में, लड़के और लड़की की शादी कराने के लिए कुछ रीति-रिवाज और दिखावटी प्रथाएँ प्रचलित हैं। शादी से पहले, दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रति इतना प्यार दिखाते हैं कि वे अपने सगे भाई-बहनों से भी अधिक एक-दूसरे को प्यार करते हैं। उनमें दुस्तरा स्नेह होता है। वे इतने उत्साहित होते हैं और एक-दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि उनका रिश्ता अटूट है। वे एक-दूसरे के नवनिर्मित भवन के निर्माण के पीछे के उद्देश्यों और उससे समाज को होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि; अहमदाबाद के जोधपुर क्षेत्र में निर्मित इस आधुनिक परिसर में सुविधाजनक गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल तथा अतिथि भवन की जोधपुर क्षेत्र में निर्मित इस आधुनिक भवन में विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ एवं स्वच्छ भोजन की व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रसोई, शांत वातावरण वाली अत्याधुनिक पुस्तकालय, पूर्णतः वाई-फाई से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, फिटनेस के लिए जिम, सैमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल तथा विशाल कम्युनिटी हॉल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 24×7 सुरक्षा व्यवस्था के साथ बेसमेंट एवं ग्राउंड फ्लोर पार्किंग जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं से इस परिसर को सज्ज किया गया है। इस लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी तथा वीबीसी समाज के अग्रणी श्री धीरज पारेख सहित गुजरात तथा देश-विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे समस्त वीबीसी परिवार के अग्रणी, श्रेष्ठी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में समाज के भाई-बहन उपस्थित रहे।

जिवाह के बाद लड़की को जिम्मेदारी बड़ जाती है और उसे छोटी-छोटी बातों पर माता-पिता से शिकायत करने के बजाय सास-ससुर को माता-पिता की तरह मानना चाहिए, जिससे घर में कलह का माहौल बन जाता है। इसी वजह से शांत घर में भी कलह शुरू हो

जाती है। अक्सर झगड़े का कोई कारण नहीं होता, लेकिन माता-पिता या किसी रिश्तेदार या बड़े के अहंकार के कारण लड़की के घर में बेवजह का हंगामा मच जाता है। जहाँ लड़की या बेटी माता-पिता की सलाह मानती है, वहाँ झगड़े जल्दी सुलझ जाते हैं। जहाँ शांति से रहने की इच्छा होती है, लेकिन जब लड़की दूध, सब्जी या किसी भी कारण से बाहर नहीं जाती, तो परिवार में झगड़े होना आश्चर्य की बात है। जब लड़की के माता-पिता कहते हैं कि मेरी बेटी और उसके दामाद के बीच कोई समस्या नहीं है, तो क्या? ऐसे आरोप सही नहीं होते। अगर लड़का नशे का आदी है और ऐसा लगता है मानो वह लड़की या ससुराल वालों की सलाह सीमित दायरे में ही होनी चाहिए। लड़की को ससुराल वालों या घर के किसी भी सदस्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार की उकसाहट से दूर रहना चाहिए। किसी भी लड़के या लड़की को अपने माता-पिता की उपस्थिति में अपनी सास के खिलाफ गुण टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि यह संयुक्त बचपन समाज में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न करने के शुभ इरादे से जारी किया गया है।

डी.सी. सोलंकी अध्यक्ष, भाई लाल बी. ण्णाव उपाध्यक्ष, बिपिनभाई राठौड़ उपाध्यक्ष कांतिभाई बी. सोलंकी महासचिव, मयंकभाई जे. सोलंकी महासचिव शशिकांत सोलंकी

सामाख्याली-गांधीधाम रेलखंड पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहगी

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत सामाख्याली, चौध एवं भचाऊ स्टेशनों के बीच चौहरिकरण (Quadrupling) एवं ऑटोमैटिक सिग्नलिंग परियोजना के कमीशनिंग कार्य के संबंध में नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य हेतु ब्लॉक लिया जा रहा है। यह कार्य सामाख्याली-गांधीधाम रेलखंड पर रेल अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा परिचालन क्षमता एवं सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के अंतर्गत नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

(A) पूर्णतः निरस्त (Fully Cancelled) ट्रेनें

- गाड़ी संख्या 09416 गांधीधाम-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल तथा गाड़ी संख्या 09415 बांद्रा टर्मिनस-गांधीधाम स्पेशल 23 एवं 30 जुलाई 2026 को निरस्त रहेगी।
- गाड़ी संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस-भुज स्पेशल 18, 23, 25 एवं 30 जुलाई 2026 को तथा गाड़ी संख्या 09038 भुज-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 19, 24, 26 एवं 31 जुलाई 2026 को निरस्त रहेगी।
- गाड़ी संख्या 12965 बांद्रा टर्मिनस-भुज एक्सप्रेस 28 जुलाई एवं 04 अगस्त 2026 को तथा गाड़ी संख्या 12966 भुज-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 24 एवं 31 जुलाई 2026 को निरस्त रहेगी।
- गाड़ी संख्या 19406 गांधीधाम-पालनपुर एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या 19405 पालनपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस 19 जुलाई से 04 अगस्त 2026 तक निरस्त रहेगी।

अधिकारी के लिए शोभा नहीं देता। उन्हें अपने एसी कार्यालय में बैठकर निजी जांच अधिकारी, पुलिस जांच अधिकारी या उनकी टीम से कार्रवाई करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के कानूनी आदेशों के अनुसार, किसी छोटे कांस्टेबल या उच्च अधिकारी द्वारा अपराधियों का जुलूस सार्वजनिक सड़क पर निकालना शर्मनाक घटना है। हम अपराधियों को संरक्षण या समर्थन नहीं देना चाहते। किसी भी अपराधी को उसके अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से अपराधी को 5-10 थप्पड़ मारने से अपराध नहीं रुकेगा। उन्हें ऐसे कागजात तैयार करने चाहिए जिससे वे उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर कानून की किसी भी खामि से बच न सकें। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे उन्हें लंबी जेल की सजा हो और अल्पकालिक जमानत न मिल सके। सार्वजनिक सड़क पर अपराधियों का वीडियो बनाना या उनकी तस्वीरें लेना जनता के मन से उनके प्रति भय दूर नहीं करेगा। उन्हें केवल उनके द्वारा किए गए अपराध से संबंधित कानून की धाराओं के अनुसार कागजात तैयार करके लंबी अवधि के लिए कारावास में डाल देना चाहिए। उनकी गरिमा तभी बहाल होगी जब उन्हें अदालत के आदेशानुसार या किसी अन्य तृतीय-श्रेणी की सजा का उपयोग करके कानून के अनुसार एक बंद कमरे में रखा जाए और उन्हें विशेष सेवा/उपचार दिया जाए ताकि वे भविष्य

देश भर में एक लाख से अधिक सरकारी स्कूल एक ही शिक्षक पर निर्भर हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं

(निर्भीक, निष्पक्ष, निष्पक्ष छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत. चाहे भारत हो या विश्व, शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों से प्राप्त ज्ञान नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे में चिंतन शक्ति, रचनात्मकता, नैतिक मूल्य, सामाजिक समझ और जीवन कौशल विकसित होते हैं। लेकिन जब एक ही शिक्षक पाँच या छह कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है, तो प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना असंभव हो जाता है। परिणामस्वरूप, शिक्षा का स्तर गिर जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों बच्चों को उठाना पड़ता है।

लेकिन जब सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के एक लाख से अधिक सरकारी स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो यह न केवल चिंता का विषय है, बल्कि इससे पूरी शिक्षा नीति पर गंभीर सवाल उठते हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जारी यूडीआरएस+ 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के एक लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक बचपन से ही ऐसे शिक्षक को एक साथ विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। उन्हें स्कूल के प्रशासनिक कार्यों के ज़िम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है। उन्हें सरकारी योजनाओं को लागू करना होता है और साथ ही चुनाव से लेकर जनगणना तक के कर्तव्यों

में कोई अन्य अपराध न करें और जीवन भर के लिए अपराध की दुनिया से विमुख हो जाएं। या फिर उन्हें इस मानसिकता में ढाल दिया जाए कि वे फिर कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी शरद सिंघल को चंदोला झील में एक छोटे अपराधी के बारे में सूचना मिली, जिसके पास देसी पिस्तौल थी। इस सूचना के आधार पर डीसीपी शरद सिंघल खुद अपनी टीम के साथ अपराधी को पकड़ने चंदोला झील गए। और कहा जाता है कि जब अपराधी ने डीसीपी शरद सिंघल पर पैडल और चाकू से जानलेवा हमला किया, तो डीसीपी शरद सिंघल ने अपने बगल में खड़े पीआई से रिवाॅल्वर छीनकर योगी की यूपी सरकार के पेटेंट की तरह अपराधी के पैर में गोली मार दी। जब तक डीसीपी शरद सिंघल ने पीआई से रिवाॅल्वर छीनकर अपराधी के पैर में गोली मारी, तब तक अपराधी पैडल और चाकू ताने वहीं खड़ा था? एक उच्च पदस्थ अधिकारी के ऐसे शब्द जनता को स्वीकार्य नहीं हैं। ठीक वैसे ही अपराध से संबंधित कानून के ऐसे शब्द जनता के स्वीकार्य नहीं हैं। ठीक वैसे ही अपराध से संबंधित कानून की धाराओं के अनुसार कागजात तैयार करके लंबी अवधि के लिए कारावास में डाल देना चाहिए। उनकी गरिमा तभी बहाल होगी जब उन्हें अदालत के आदेशानुसार या किसी अन्य तृतीय-श्रेणी की सजा का उपयोग करके कानून के अनुसार एक बंद कमरे में रखा जाए और उन्हें विशेष सेवा/उपचार दिया जाए ताकि वे भविष्य

में कोई अन्य अपराध न करें और जीवन

भर के लिए अपराध की दुनिया से विमुख हो जाएं। या फिर उन्हें इस मानसिकता में ढाल दिया जाए कि वे फिर कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी शरद सिंघल को चंदोला झील में एक छोटे अपराधी के बारे में सूचना मिली, जिसके पास देसी पिस्तौल थी। इस सूचना के आधार पर डीसीपी शरद सिंघल खुद अपनी टीम के साथ अपराधी को पकड़ने चंदोला झील गए। और कहा जाता है कि जब अपराधी ने डीसीपी शरद सिंघल पर पैडल और चाकू से जानलेवा हमला किया, तो डीसीपी शरद सिंघल ने अपने बगल में खड़े पीआई से रिवाॅल्वर छीनकर योगी की यूपी सरकार के पेटेंट की तरह अपराधी के पैर में गोली मार दी। जब तक डीसीपी शरद सिंघल ने पीआई से रिवाॅल्वर छीनकर अपराधी के पैर में गोली मारी, तब तक अपराधी पैडल और चाकू ताने वहीं खड़ा था? एक उच्च पदस्थ अधिकारी के ऐसे शब्द जनता को स्वीकार्य नहीं हैं। ठीक वैसे ही अपराध से संबंधित कानून के ऐसे शब्द जनता के स्वीकार्य नहीं हैं। ठीक वैसे ही अपराध से संबंधित कानून की धाराओं के अनुसार कागजात तैयार करके लंबी अवधि के लिए कारावास में डाल देना चाहिए। उनकी गरिमा तभी बहाल होगी जब उन्हें अदालत के आदेशानुसार या किसी अन्य तृतीय-श्रेणी की सजा का उपयोग करके कानून के अनुसार एक बंद कमरे में रखा जाए और उन्हें विशेष सेवा/उपचार दिया जाए ताकि वे भविष्य

का निर्वाह भी करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना कितना व्यावहारिक है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का सपना प्रस्तुत किया है। लेकिन ये सुंदर नीतिगत दस्तावेज तभी सार्थक होते हैं जब पर्याप्त शिक्षक हों, उचित बुनियादी ढांचागत सुविधाएँ हों और प्रभावी कार्यान्वयन हो। शिक्षकों के बिना या केवल एक शिक्षक पर आधारित विद्यालय किसी भी शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी विशेष रूप से गंभीर है। जहां शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां सुविधाओं की न्यूनतम उपलब्धता विकास की संभावनाओं को कमजोर करती है। शिक्षकों के पद वर्षों तक खाली पड़े रहते हैं। तबादलों की नीति में असंतुलन है

प्रशंसा पाएँ। गृह मंत्री और सरकार यह साबित करना चाहते हैं कि हमारी सरकार और हमारे पुलिस अधिकारी जनता के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन यह सब झूठी प्रशंसा पाने और खुद का प्रचार करने का प्रयास है। जैसे सूरत में फिलहाल 42 पुलिस थानों के प्राइवेट जासूस, पीएसआई या कर्मचारी, अपराध (डीसीबी) शाखा के अधिकारी, इकोसेल, साइबर क्राइम, पीसीबी जैसी विभिन्न शाखाओं के अधिकारी या स्थानीय स्तर के अधिकारी आपराधिक गतिविधियों को दबाने में लगे रहते हैं। लेकिन सूरत में कुछ अलग ही चल रहा है। यहां तक कि एसओजी के कार्यक्षेत्र में शामिल न होने वाले काम भी एसओजी के डीसीपी नाकुम कर रहे हैं, चाहे वह नासिरनगर का धिर्वंस हो या जमानत पर रिहा हुए छोटे-बड़े अपराधों के अपराधियों को एसओजी थाने बुलाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से 5-10 कोड़े मारना, ताकि उनका नाम सरकार की नजरों में आए या जनता से प्रशंसा मिले। गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री को एसओजी के डीसीपी नाकुम जैसे अधिकारियों का तबादला गुजरात के संवेदनशील क्षेत्रों में करना चाहिए, जहां वे गुजरात में अशांति फैलाने वाले, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले, गुजरात सीमा पर बड़े अपराध करने वाले या करोड़ों रुपये की की मानसिकता यही है कि वे सरकार की नजरों में अपना नाम दर्ज कराएं, सरकार से पुरस्कार प्राप्त करें और जनता से

प्रशंसा पाएं। गृह मंत्री और सरकार यह

साबित करना चाहते हैं कि हमारी सरकार और हमारे पुलिस अधिकारी जनता के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन यह सब झूठी प्रशंसा पाने और खुद का प्रचार करने का प्रयास है।

जैसे सूरत में फिलहाल 42 पुलिस थानों के प्राइवेट जासूस, पीएसआई या कर्मचारी, अपराध (डीसीबी) शाखा के अधिकारी, इकोसेल, साइबर क्राइम, पीसीबी जैसी विभिन्न शाखाओं के अधिकारी या स्थानीय स्तर के अधिकारी आपराधिक गतिविधियों को दबाने में लगे रहते हैं। लेकिन सूरत में कुछ अलग ही चल रहा है। यहां तक कि एसओजी के कार्यक्षेत्र में शामिल न होने वाले काम भी एसओजी के डीसीपी नाकुम कर रहे हैं, चाहे वह नासिरनगर का धिर्वंस हो या जमानत पर रिहा हुए छोटे-बड़े अपराधों के अपराधियों को एसओजी थाने बुलाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से 5-10 कोड़े मारना, ताकि उनका नाम सरकार की नजरों में आए या जनता से प्रशंसा मिले। गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री को एसओजी के डीसीपी नाकुम जैसे अधिकारियों का तबादला गुजरात के संवेदनशील क्षेत्रों में करना चाहिए, जहां वे गुजरात में अशांति फैलाने वाले, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले, गुजरात सीमा पर बड़े अपराध करने वाले या करोड़ों रुपये की दस की मानसिकता यही है कि वे सरकार की नजरों में अपना नाम दर्ज कराएं, सरकार से पुरस्कार प्राप्त करें और जनता से

और नई भत्तियों में देरी होती है। इन समस्याओं का सीधा शिकार छात्र होते हैं। अंततः, सवाल सिर्फ एक लाख स्कूलों का नहीं है। सवाल लाखों बच्चों के भविष्य है। एक ऐसे देश में जहां हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का संकल्प है, वहां एक ही तरह की शिक्षा देने वाले स्कूलों का अस्तित्व ही नीति और उसके क्रियान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करता है। अगर सरकार के लिए इस चुनौती को गंभीरता से लेने और त्वरित एवं प्रभावी कदम उठाने का समय है। क्योंकि सशक्त शिक्षकों के बिना सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, सशक्त शिक्षा के बिना नहीं। क्योंकि भारत एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक छात्र आबादी वाले देश में, शिक्षा प्रणाली की मजबूती ही विकास का सच्चा आधार है।

गाड़ी संख्या 14311 बरेली-भुज एक्सप्रेस 01 अगस्त 2026 को अहमदाबाद स्टेशन पर शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा भुज-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 22 एवं 29 जुलाई 2026 को निरस्त रहेगी।

28 जुलाई 2026 को अहमदाबाद स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा अहमदाबाद-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 22903 बांद्रा टर्मिनस-भुज एसी एक्सप्रेस 31 जुलाई एवं 02 अगस्त 2026 को अहमदाबाद स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा अहमदाबाद-भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी एवं गाड़ी संख्या 22904 भुज-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 01 एवं 03 अगस्त 2026 को अहमदाबाद स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा भुज-अहमदाबाद के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 11092 पुणे-भुज एक्सप्रेस 03 अगस्त 2026 को अहमदाबाद स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा अहमदाबाद-भुज के बीच आंशिक निरस्त रहेगी एवं गाड़ी संख्या 11091 भुज-पुणे एक्सप्रेस 05 अगस्त 2026 को अहमदाबाद स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा भुज-अहमदाबाद के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 20936 इंदौर-गांधीधाम एक्सप्रेस 02 अगस्त 2026 को अहमदाबाद स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा अहमदाबाद-गांधीधाम के बीच आंशिक निरस्त रहेगी एवं गाड़ी संख्या 20685 गांधीधाम-केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस 04 अगस्त 2026 को अहमदाबाद स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा भुज-अहमदाबाद के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 16335 गांधीधाम-नागरकोइल एक्सप्रेस 31 जुलाई 2026 को अहमदाबाद स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा भुज-अहमदाबाद के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 16336 नागरकोइल-गांधीधाम एक्सप्रेस